पुलिस एवं राजनीतिक संरक्षण में पलता एक गुनाहों का देवता

अवैध हथियारों व चोरी की बिजली से पानी का धंधा करने वाले की शिकायत करना महंगा पड़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) पुलिस चौकी सेक्टर 7 के इलाके में स्थित इन्दरा कॉलोनी में रहने वाले ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान वासदेव अहेरिया को अपने पड़ोस में रहने वाले शामबीर की आपराधिक करतूतों की पुलिस को शिकायत करना काफ़ी महंगा पड़ गया। दिनांक 20 अगस्त को प्रात: 7 बजे जब अहेरिया अपने काम पर जा रहे थे तो शामबीर व उसके भाईयों ने उन पर पीछे से लोहे के पाइप व डंडे लाठियों से हमला कर दिया। यदि पास पड़ोस के लोग बीच-बचाव न कराते तो शायद यह भी एक मॉब लिंचिंग का केस बन जाता। फ़िर भी अहेरिया के बांये हाथ की हड्डी (कंधे व कोहनी के बीच वाली) बुरी तरह से टूट गयी। उन्हें तुरंत बीके अस्पताल पहुंचाया गया जहां 23 तारीख को उनका ऑपरेशन करके प्लेट डाल कर हड्डी जोड़ी गयी है। इसे पूरी तरह जुड़ने में करीब एक वर्ष लग सकता है। शरीर पर लगी गुम चोटों का तो हिसाब ही नहीं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की साधारण धाराओं 323 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर

एससी/एसटी एक्ट का गरीबों को कोई लाभ नहीं

लिया गिरफ़्तारी कोई नहीं।

अहेरिया से शामबीर की दुश्मनी पुरानी है। वह पहले भी उन पर छोटे-मोटे हमले कर चुका है। लेकिन पुलिस ठोस कार्यवाही की बजाय समझौता करा कर मामले को रफ़ा-दफ़ा कराती रही है। दुश्मनी का कारण अहेरिया द्वारा शामबीर के काले धंधों की शिकायत पुलिस को करना है।

अपने आपको भाजपा का मंडल अध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक एवं मंत्री विपुल गोयल का खास आदमी बताने वाले शामबीर का पुराना धंधा अवैध शराब व हथियार बेचने का रहा है। एक अवैध पिस्तौल तो कुछ समय पूर्व सीआईए ने इससे पकड़ा भी था। लेकिन आजकल इसका मुख्य धंधा पानी बेचने का है। जी हां सरकार की लापरवाही एवं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जगह-जगह पानी-माफ़िया पनप रहे हैं। ऐसा ही एक पानी माफ़िया शामबीर भी इस कॉलोनी में पनप चुका है।

इसने पानी सप्लाई के लिये बाकायदा पाइप लाइन बिछा कर अपने अवैध बोर से जोड़ा हुआ है जिसे चोरी की बिजली से चलाया जाता है। कई बार बिजली वालों ने इसे पकड़ा भी है लेकिन ढाक के वही तीन पात। घरों में सप्लाई होने वाले इस पानी के बदले शामबीर प्रत्येक घर से 600 से लेकर 1500 रुपये तक कुछ भी वसूल कर सकता है। इस वसूली का रेट उस घर में रहने वालों की संख्या पर निर्भर कराता है। जो समय पर पेमेंट न करे तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। दोबारा जोड़ने का जुर्माना अलग से वसूला जाता है।

अपने पानी पर कॉलोनी वासियों की निर्भरता को बढाने के लिये शामबीर नगर निगम के सरकारी ट्यूबवैल चालक से भी सांठ-गांठ करके उस ट्यूबवैल अक्सर दो-चार दिन के लिये 'खराब' करवा देता है। इस बाबत शुरू में तो कॉलोनीवासियों ने निगम अधिकारियों को कई बार शिकायतें भी की लेकिन उनकी बेरूखी व शामबीर की गुंडई के चलते उन्होंने हालात से इस कदर समझौता कर लिया है कि वे शामबीर की किसी भी बदमाशी के विरुद्ध मुंह नहीं खोलते।

विदित है कि किसी भी इलाके में किसी भी गुंडे को गुंडागर्दी करने का साहस तभी हो पाता है जब स्थानीय पुलिस से उसकी अच्छी सांठ-गांठ हो। जाहिर है पुलिस से यह सांठ-गांठ तभी संभव हो पाती है जब गुंडा पुलिस की लूट कमाई में सहयोग करे। कोई भी गुंडा कभी अपनी जेब से पुलिस को कुछ नहीं देता। हां अपने लूट के धंधे से कुछ थोड़ा बहुत देने के अलावा पुलिस की दलाली के माध्यम से उसकी सेवा करता है। दोषी शामबीर के साथ पुलिस का बर्ताव भी ऐसे ही संकेत दे रहा है। यदि शामबीर पुलिस का कृपा पात्र न होता तो सर्वप्रथम उसके विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट की धारा लगायी जानी चाहिये थी क्योंकि अहेरिया दलित जाति से सम्बंधित है इसके अलावा हड्डी टुटने की धारा भी लगा कर शमबीर व उसके भाईयों और साथियों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिये था, जो पुलिस ने नहीं किया।

शिक्षा विभाग के तुगलकी फ़रमानों से कॉलेज छात्र और शिक्षक सभी परेशान

फरीदाबाद (अजातशत्रु) उच्च अधिकारियों द्वारा अपने आपको खट्टर सरकार का ज्यादा बड़ा ताबेदार दिखाने के चक्कर में रोज-रोज ऐसे आदेश ज़ारी किये जा रहे हैं कि सभी कॉलेजों में अफ़रा-तफ़री मची हुई है, सभी परेशान हैं।

वास्तविक समस्या कॉलेजों में प्राध्यापकों की भारी कमी है। थोड़ी-बहुत नयी नियुक्तियां करने के बावजूद अभी भी प्राध्यापकों के लगभग आधे पद रिक्त हैं। उन पदों पर नियमित प्राध्यापक नियुक्त करके भरना असली समाधान है। लेकिन नौकरियां देने और वो भी शिक्षा विभाग जैसे गैर कमाऊ पूत को उसमें हुड्डा की नानी मरती थी और खट्टर की भी।

नियमित प्राध्यापकों की कमी को पहले 'गेस्ट टीचर ' और 'विजिटिंग टीचर' भर्ती करके पूरा कर लिया जाता था। हालांकि इन बेचारे गेस्ट और विजिटिंग प्रोफ़ेसर का बेहद शोषण किया जाता था, उनसे पूरा काम लेकर तनखा चपरासी से भी कम दी जाती है। लेकिन वो खर्च भी सरकार को नागवार गुजरा। इसलिये पिछले कुछ सालों से ऊपर बैठे गुलाम अफ़सरों ने इस समस्या का एक नया तुगलकी इलाज ढूंढ निकाला-डेपूटेशन का। यानी एक लेक्चरर तीन दिन एक कॉलेज में पढायेंगे तो तीन दिन दूसरे में। और उसे दोनों कॉलेजों में पूरा सिलेबस पढाना है। स्पष्ट है कि ये उन नियमित प्राध्यापकों का भी शोषण है क्योंकि उनसे उसी पगार में दुगुना काम लिया जा रहा है और ऊपर से दूसरे कॉलेज में आने-जाने का हजारों रुपया महीना का खर्चा अलग से। लेकिन अब तो बात बिल्कुल ही महामूर्खता की तरफ़ बढ गयी है।

इस साल आयी डेपूटशन की लिस्टों में शायद ही किसी प्राध्यापक को बख्शा गया हो लगभग सभी को वो दो कॉलेजों में पढाना है। अगर आपकी सिफ़ारिश है तो आपको दूसरा कॉलेज कोई नजदीक दे देंगे नहीं तो दूर पटक देंगे। कई प्राध्यापकों को तो 70 से 100 कि.मी. की दूरी तक दूसरे ज़िलों में भी डेपूटेशन पर भेजा गया

इस साल 27 जुलाई को आई लिस्ट में एक ऐसे प्राध्यापक को भी डेपूटेशन पर भेज दिया जो उसी महीने, यानी चार दिन बाद 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे। इसके अलावा दूसरे ज़िलों में और उस विषय की दूसरे कॉलेज में क्लास न होने पर भी नियुक्ति के अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल अभी आयी लिस्टों में पायी गयी कि कई प्राध्यापकों को हफ़्ते में छ: के छ: दिन दूसरे कॉलेज में पढाने के आदेश दिये गये हैं। जाहिर है कि इन आदेशों से पहले वाले कॉलेज में पढाई ठप्प हो जायेगी। एक अन्य लेक्चरर का डेपूटेशन फ़रीदाबाद से नचौली गणित विषय में कर दिया जबकि वहां गणित विषय है ही नहीं।

है। यानी तीन दिन वो एक कॉलेज में पढायें और तीन दिन दूसरे कॉलेज में 100 कि.मी. दूर। उसका ये दो जगह घर बसाने या सफ़र का खर्चा कौन देगा इस पर ऊपर बैठे अफ़सर मौन हैं।

इस साल 27 जुलाई को आई लिस्ट में एक एक ऐसे प्राध्यापक को भी डेपूटेशन पर भेज दिया जो उसी महीने, यानी चार दिन बाद 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे। इसके अलावा दूसरे ज़िलों में और उस विषय की दूसरे कॉलेज में क्लास न होने पर भी नियुक्ति के अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन सबसे बड़ी मूख अभी आयी लिस्टों में पायी गयी कि कई प्राध्यापकों को हफ़्ते में छ: के छ: दिन दूसरे कॉलेज में पढाने के आदेश दिये गये हैं। जाहिर है कि इन आदेशों से पहले वाले कॉलेज में पढाई ठप्प हो जायेगी। एक अन्य लेक्चरर का डेपूटेशन फ़रीदाबाद से नचौली गणित विषय में कर दिया जबकि वहां गणित विषय है ही नहीं। जाहिर है कि वो प्राध्यापक तीन दिन अब वहां नचौली पढ़ायेगा नहीं क्योंकि विषय नहीं है और फ़रीदाबाद से तीन दिन वो डेपूटेशन पर है इसलिये उसे बैठे बिठाये तीन दिन छुट्टी मिल गयी। इसके अलावा फ़रीदाबाद सैक्टर 16 ए के दोनों कॉलेजों से लगभग चार प्राध्यापकों को छ:महीने के लिये हफ़्ते में छहों दिन खेड़ी गुजरान पढाने के लिये भेज दिया जबकि यहां इन कॉलेजों में वर्क लोड बहुत ज्यादा है और पढाने वाला दूसरा कोई प्राध्यापक नहीं है। इससे सवाल यह उठता है कि क्या खेड़ी गुजरान् के विद्यार्थी वीआईपी हैं जो उनकी पढाई का तो प्रबंध होना चाहिये सैक्टर 16 ए वाले जायें भाड़ में। ऐसे लगता है कि जैसे प्राध्यापकों की लूटपाट मची हुई है। जो प्रिंसिपल ताकतवर/पहुंच वाला है उसने ज्यादा लैक्चरर लूट लिये और जो कमजोर थे वो रह गये। उनके छात्र जाये भाड़ में।

यह भी पता चला है कि 29 अगस्त को राजकीय महिला महाविद्यालय से 16 ए की सभी टीचरों की बदली हो गयी है तो छात्राओं ने काफ़ी हल्ला मचाया। उन्होंने लिखित में एक आवेदन प्रिंसिपल को दिया कि उनकी मैडमों का तबादला रोका जाये। वहां से कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वो जूलूस लेकर मंत्री विपुल गोयल के घर सैक्टर 17 पहुंच गयी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है ऐसे 'तुच्छ' लोग़ों से मिलने के लिये मंत्री जी घर पर नहीं थे। इसलिये सभी छात्रायें मायूस अपने-अपने घरों को चली गई। बाकि प्रिंसिपल भगवती राजपूत की तो हिम्मत ही कहां है जो ऊपर वाले अफ़सरों से बात-चीत करे क्योंकि वो तो पहले पेड़ चोरी के मामले में ऊपर वालों का बहुत एहसान लिये बैठी है। और वैसे भी दिसम्बर में उसकी रिटायरमेंट है तो वो तो चुपके से अपने दिन पूरे कर रही है। स्टाफ़ की इतनी भारी कमी के बावजूद 31 नये कॉलेज खोलना ये दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ़ पैसे खाने के लिये कॉलेज खोल रही है न कि हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिये। ऊपर से रही-सही कसर उपर बैठे चापलूस अफ़सर इन तुगलकी फ़र्मानों से पूरी कर रहे हैं।

पहले ऑन-लाइन एडमिशन अब ये डेपूटेशन-लगता है हरियाणा में कॉलेज शिक्षा की तबाही बहुत जल्दी तय है

७

'आयुष्मान भारत' का बीके अस्पताल

फ़रीदाबाद (म.मो.) भाजपा की मोदी व खट्टर सरकार 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत हरियाणा की 15 लाख अति गरीब जनता को 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज देने का ढोल पुरे ज़ोर-शोर से पीट रहे हैं जबकि धरातल पर इनके पास देने को कुछ भी नहीं है। 20 लाख की आबादी वाले शहर फ़रीदाबाद में खट्टर सरकार का एक ज़िला अस्पताल बादशाहखान के नाम से चल रहा है। इसमें गत तीसियों वर्ष से केवल 200 बिस्तरों का ही इंतज़ाम है। इनके लिये भी यहां न तो पर्याप्त डॉक्टर है न अन्य स्टॉफ़ व उपकरण और दवायें हैं। और तो और मरीज़ों को लाने ले जाने के लिये न तो ब्हील चेयर हैं न ही स्ट्रेचर। स्ट्रेचरों की कमी के चलते एक ही स्ट्रेचर पर दो-दो मरीज़ों को डाला जाता है।

चार मंजिला अस्पताल में ऊपर-नीचे आने-जाने के लिये लगायी गयी एक मात्र लिफ़्ट भी अक्सर बिगड़ी ही रहती है। ऐसे में चल पाने में असमर्थ मरीज़ों को लाने ले जाने के लिये उनके परिजन जैसे-तैसे उठा कर ले जाते हैं। जब भी लिफ़्ट के बारे में अस्पताल प्रशासन से पूछा जाता है तो एक ही रटा-रटाया जवाब मिलता है कि सम्बंधित कम्पनी को पत्र लिख दिया गया है और वे जल्दी ही आकर इसे ठीक कर देंगे। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है लेकिन स्थाई समाधान कोई नहीं हो रहा।

गत सप्ताह यानी 23 अगस्त को हड्डी का ऑपरेशन कराने के बाद वार्ड में पहुंचे वासदेव अहेरिया ने बताया कि वहां चूहों का पूरा आतंक है रात भर बिस्तरों पर उछल-कुद मचाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनको लगायी गयी एक खून की थैली को भी चूहे काट गये। रात को जब भी आंख लगती चूहों के उत्पात से निंद खुल जाती। तीन दिन भी अस्पताल में काटने भारी हो गये।

बिजली का संकट तो यहां पर स्थाई रूप से बना ही रहता है। यहां की सारी वायरिंग निहायत ही घटिया एवं मानकों के विपरीत है यानी कि जितना लोग वहन करने की क्षमता इन लाईनों में होनी चाहिये वह नहीं है। इसके चलते इन लाईनों में अक्सर आग लगती रहती है और एक बार आग लगने का मतलब अस्पताल में कई-कई घंटों के लिये बिजली गुल हो जाती है। पिछे से बिजली सपलाई बंद होने की स्थिति से निपटने के लिये कहने को तो यहां जनरेटरों की व्यवस्था है परन्तु या इनके लिये डीजल नहीं होता या कोई अन्य खराबी रहती है।

ओपीडी हॉल इस तरह से डिज़ायन किया गया है कि उसमें न बाहर से हवा आ सकती है न रोशनी। बिजली गुल होने की स्थिति में वहां घुप अंधेरा तो होता ही है तथा गर्मी से भी लोग बेहाल होते हैं। इस हॉल में सदैव क्षमता से कहीं अधिक मरीज़ लाईनों में खड़े देखे जा सकते हैं। समझा जा सकता है कि बिजली गुल होने पर इन लोग़ों के साथ क्या बीतती होगी।

क्या मोदी व खट्टर सरकार इसी अस्पताल के दम पर 'आयुष्मान भारत' योजना चलायेंगे ? विदित है कि देश भर के तमाम निजी अस्पतालों ने 'आयुष्मान' के तहत सरकार से अनुबंध करने से इनकार कर दिया है। थोड़ी बहुत आशा की किरण ईएसआई निगम के अस्पतालों में हो सकती थी लेकिन सरकार ने समय रहते इनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। सेक्टर 8 स्थित ईएसआई अस्पताल की क्षमता 200 बेड की है लेकिन इसमें केवल 50 बेड ही उपलब्ध कराये गये हैंऔर इनमें से भी लगभग 40 बेड हर समय खाली ही पड़े रहते हैं। क्योंकि वहां चिकित्सा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी ही हालत ईएसआई की तमाम डिस्पेंसरियों की भी है।

जाहिर है कि ऐसे में मोदी का 'आयुष्मान भारत' एक जुमला बनकर ही रह जायेगा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06